लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2896

04 जनवरी, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

तकनीकी वस्त्र क्षेत्र

2896. श्री हरि मांझीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में मौजूदा अवसरों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को मजबूत करने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री अजय टम्टा)

(क) और (ख): जी, हां। भारत सरकार ने तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं:-

i. **तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी):** टीएमटीटी, वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक क्रियान्वित किया गया है। तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को परीक्षण सुविधाएं, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, कौशल विकास सुविधाएं प्रदान करने के लिए नौ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) 156 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए गए। तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संभावित उद्यमियों की सहायता करने के उद्देश्य से 59.35 करोड़ रुपए की लागत से तकनीकी अनुसंधान संघों और आईआईटी में प्लग एंड प्ले मॉडल पर 11 फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) स्थापित किए जा रहे हैं।

ii. **एग्रो टेक्सटाइल्स के प्रयोग के लिए योजना:** यह योजना 65 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2012-13 से 2018-2019 के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों, उपयोग के लिए उपयुक्त एग्रो टेक्सटाइल उत्पादों के विकास और इस क्षेत्र के लिए एग्रो टेक्सटाइल उत्पादों के उपयोग के लाभ को दर्शाने वाली प्रदर्शन व्यवस्था की सृजन के माध्यम से कृषि, बागवानी तथा फूलों की खेती के उत्पादन में एग्रो टेक्सटाइल के उपयोग को बढ़ावा देना है।

8 पूर्वोत्तर राज्यों में अभी तक 44 प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं और किसानों को 742 एग्रो टेक्सटाइल किटें वितरित की गई हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 10 प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं और 200 एग्रो टेक्सटाइल्स किटें किसानों को वितरित की गई हैं।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग संबंधी संवर्धन योजना: यह योजना 427 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क विकास, पहाड़ी/ढलान सुरक्षा तथा जलाशयों की मौजूदा/नई परियोजनाओं में जैव वस्त्रों के उपयोग के कारण वृद्धिशील लागतों, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करके अवसंरचना के विकास में एग्रो टेक्सटाइल का संवर्धन और उपयोग करना है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों में अभी तक 98.19 करोड़ रुपए की लागत से 34 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ग): वस्त्र मंत्रालय द्वारा किए गए तकनीकी वस्त्र उद्योग के बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग के वर्ष 2017-18 तक 12% सीएजीआर पर वृद्धि करते हुए 1,16,217 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसके, वर्ष 2020-21 तक 20% की सीएजीआर से 2,00,823 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है।

*****